महाराष्ट्र वक्फ संपत्ति बिक्री मामले में ईडी ने की छापेमारी

● ऐसी कार्रवाइयों से डरता नहीं, छापेमारी के बाद मलिक ने कहा

भाषा। नई दिल्ली/मुंबई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की कथित गैर-कानूनी बिक्री से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को पुणे और इसके आसपास के इलाकों में कई परिसरों की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि कम से कम सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया और धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत कार्वाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी का धन शोधन मामला महाराष्ट्र पुलिस की प्राथमिकी और आरोपपत्र पर आधारित है और एजेंसी छापेमारी के जरिए और अधिक जानकारी जुटा रही है।

वहीं वक्फ संपत्तियों की कथित अवैध बिक्री से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा महाराष्ट्र में कई परिसरों पर छापेमारी किए जाने के बाद, राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय एजेंसी इस गलतफहमी में है कि वह उन्हें इस तरह के कार्यों से डरा सकती है। मलिक ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय एजेंसी का उपहास उड़ाया और कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली 30,000 संस्थाओं की जांच किए जाने का स्वागत है। वक्फ बोर्ड ईडी को सभी आवश्यक सहयोग देगा। मंत्री ने कहा, हालांकि इसे शिया वक्फ बोर्ड, लखनऊ द्वारा की गई शिकायतों की भी उतनी ही दिलचस्पी से जांच करनी चाहिए।

मलिक ने कहा, अगर ईडी को लगता है कि इस तरह की कार्वाई (छापेमारी) से मैं डर जाउंगा, तो यह गलतफहमी है। इस तरह की कार्वाइयां मुझे उस सफाई अभियान को जारी रखने से नहीं रोकेंगी जिसके तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। भाजपा की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) मंत्री ने कहा कि वह अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ ईडी को "कुछ नेताओं के दस्तावेजों की एक सूची भेजेंगे और एजेंसी से उनकी जांच करने का आग्रह करेंगे। मलिक भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों, विशेष रूप से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के कथित दुरुपयोग के लिए मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं।

केंद्र की पहलों के क्रियान्वयन की निगरानी करें राज्यपाल: नायडू

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यों के राज्यपालों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से बृहस्पतिवार को अपील की कि वे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करने और राष्ट्र-निर्माण की पहलों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में अग्रसक्रिय भूमिका निभाएं। नायडू ने यहां राज्यपालों और उपराज्यपालों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उनसे अपील की कि वे प्रभावी जन भागीदारी के साथ राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सबका साथ-सबका प्रयास के दर्शन से प्रेरित केंद्र सरकार की पहलों की निगरानी करें और उनका मार्गदर्शन करें।

नायडू ने पर्यावरणीय सुरक्षा, किसानों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और जनजीवन में संवैधानिक मूल्यों एवं नीतियों को बढ़ावा देने समेत कई मामलों पर अपने विचार रखे। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक जीवन में राज्यपालों के विशाल अनुभव का उल्लेख करते हुए जोर देकर कहा कि नीतियों को आकार देने और उनके निष्पादन, दुर्लभ संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी एवं नैतिकता सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नायडू ने कहा, राज्यपालों और उपराज्यपालों को न केवल एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में, बल्कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के नैतिक प्राधिकार के साथ काम करना चाहिए। राज्यपालों और उपराज्यपालों को बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण, संस्कृति और प्रकृति का संरक्षण की दिशा में योगदान देना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की भी अपील की।

भोपाल में सहस्रबाहु कलचुरी महासभा के सदस्य सहस्त्रबाहु जयंती के अवसर पर शाहपुरा सरोवर के तट पर दीप जलाते हुए।

क्रूज मादक पदार्थ मामले में गवाह प्रभाकर सैल एनसीबी के समक्ष पेश हुआ

भाषा। मुंबई

स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल बृहस्पतिवार को क्रूज पर कथित मादक पदार्थ जब्ती से जुड़े मामले की जांच कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के समक्ष पेश हुआ। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान का बेटा आर्यन खान भी आरोपी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सैल ने दावा किया था कि उसने आर्यन खान को मामले से निकालने के लिए पैसे के लेन-देन की बात सुनी थी। सैल से पूर्व में एनसीबी की सतर्कता टीम भी पूछताछ कर चुकी है।

सैल और उनके वकील तुषार खंडारे अपराह्न करीब ढाई बजे एनसीबी के दक्षिण मुंबई कार्यालय पहुंचे। एनसीबी की दिल्ली से आई टीम ने सैल को तलब किया था जोकि अब आर्यन खान के मामले समेत कई अन्य मामलों की जांच कर रही है। एनसीबी की सतर्कता टीम ने सोमवार और मंगलवार को कई घंटे तक सैल से पूछताछ की थी। खुद को एनसीबी के गवाह के पी गोसावी का अंगरक्षक बताने वाले सैल ने पिछले महीने एक हलफनामे में दावा किया था कि क्रूज मादक पदार्थ मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उसने 25 करोड़ रुपए के लेन-देन की बात सुनी थी।

सैल ने यह भी दावा किया था कि गोसावी ने कहा था कि रकम में से आठ करोड़ रुपए एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े को दिए जाने हैं। सैल के आरोपों के बाद एनसीबी की सतर्कता टीम ने जांच शुरू की है। हालांकि, वानखेड़े ने सभी आरोपों को खारिज किया है।

जम्मू-कश्मीर में 3,195 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर ई-शासन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के प्रयासों के मद्देनजर प्रशासन भारत ब्रॉडबैंड स्कीम (बीबीएस) के अंतर्गत 3,195 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को इटरनेट सुविधा मुहैया कराएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर में तवी रिवर फ्रंट के विकास और भारत नेट योजना के कार्यान्वयन से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में बीबीएस के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को सूचित किया गया कि 408 ग्राम पंचायतों और 14 प्रखंड मुख्यालयों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है 658 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) सक्षम बनाया गया है।

मणिपुर में भाजपा के विधायकों पर राज्यपाल जल्द निर्णय लेंगे: मेहता

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय को बृहस्पतिवार को आश्वस्त किया गया कि लाभ के पद प्रकरण में भाजपा के 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में निर्वाचन आयोग की राय पर मणिपुर के राज्यपाल शीघ्र ही कोई निर्णय लेंगे। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरात्न की पीठ को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह आश्वासन दिया। इससे पहले पीठ ने सॉलिसीटर जनरल से राज्यपाल के निर्णय के बारे में प्रश्न किया था। पीठ ने कहा, निर्वाचन आयोग ने जनवरी माह में राय व्यक्त की थी। अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्यपाल को निर्णय मानना होगा। बीते 11 माह में कुछ नहीं हुआ। हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते लेकिन अपने कार्यालयों को यह सूचित कर दीजिए....।

इस पर सॉलिसीटर जनरल ने कहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम कुछ करेंगे और कोई निर्देश पारित करने की जरूरत नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले कहा था कि मणिपुर के राज्यपाल लाभ के पद मामले में भाजपा के 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय को लेकर बैठे नहीं रह सकते। शीर्ष अदालत ने ए टिप्पणी उस वक्त की जब उसे सूचित किया गया कि राज्यपाल ने 13 जनवरी 2021 के निर्वाचन आयोग की राय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। शीर्ष अदालत कारोंग से विधायक डी डी थैसी और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 12 विधायकों को इस आधार पर अयोग्य घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया था कि वे संसदीय सचिवों के पद पर हैं जो लाभ के पद के समान है। विधायक थैसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपने तर्क में कहा था कि राज्यपाल निर्णय को लटकाए नहीं रख सकते और वह विचार जानने के हकदार हैं।

मणिपुर से भाजपा के 12 विधायक कथित तौर पर 2018 के लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए जाने के मामले का सामना कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने विधायकों को नियमों का उल्लंघनकर्ता नहीं माना था क्योंकि वे राज्य में दो कानूनों द्वारा प्रदत्त छूट के तहत संसदीय सचिव के पद पर आसीन थे। इन कानूनों को बाद में उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। न्यायालय द्वारा इन कानून को निरस्त किए जाने के बाद मणिपुर कांग्रेस ने राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला के समक्ष याचिका दायर कर भापजा के 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल ने इस मामले में पिछले साल अक्टूबर में निर्वाचन आयोग से राय मांग थी। बताते हैं कि आयोग ने इस साल जनवरी में राज्यपाल को एक पत्र लिखकर उन्हें अपनी राय से अवगत कराया था।

MOULIN COMMERCIAL LIMITED
CIN: L74899DL1982PLC067811
Regd. Office: 1, Anand Gram, Aya Nagar Mehrauli, Gurgaon Road Delhi-110047
Email Id: kohli@vinylgroup.com; Website: www.moulin.co.in
Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Second Quarter and Half year Ended September 30, 2021
(In Lacs)

Particular	Quarter Ended		Half Year Ended
	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 ((Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)
Total Income from Operations	29.13	23.68	57.08
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7.35	3.41	15.45
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.35	3.41	15.45
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.74	2.50	11.44
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.65	2.50	13.35
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	57.30	57.30	57.30
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic :	1.40	0.44	1.40
2. Diluted:	1.40	0.44	1.40

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the audited standalone financial Results for the Second quarter and half year ended September, 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Second quarter and half year ended September, 30, 2021 is available on the Stock Exchanges' website (www.cseindia.com) and Company's website (www.moulin.co.in).
2. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 11th November, 2021.

For MOULIN COMMERCIAL LIMITED
Sd/-
Ashish Gupta
Managing Director
DIN -00115090
Place: Delhi
Date: 11th November, 2021

गोपाष्टमी के अवसर पर वृन्दावन में भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में गाय की पूजा करते हुए बच्चे

सोनिया से मिले गहलोत, बोले- मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला आलाकमान पर छोड़ा

नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में फैसला उन्होंने आलाकमान पर छोड़ दिया है। गहलोत ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने विचार पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखे हैं, आपस में हुई बातचीत के आधार पर जो भी फैसला होगा, वह सबको मंजूर होगा। इससे पहले, अशोक गहलोत की यहां पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ लंबी बैठक हुई जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जल्द ही अंतिम निर्णय होने की संभावना है।

गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक से पहले, उनके प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बुधवार को वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद पायलट ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने वाले कार्यकर्ताओं को भागीदारी मिलनी चाहिए और यह काम जल्द होना चाहिए। सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा, यह आलाकमान तय करेगा कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। हमने इसे आलाकमान पर छोड़ दिया। प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजस्थान आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष से बात करेंगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल के साथ विचार-विमर्श करेंगे और जो आपस में बातचीत हुई है, उसके आधार पर जो फैसला होगा, वह हम सबको मंजूर होगा। हालिया विधानसभा उपचुनावों में दोनों सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत का उल्लेख करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि अब भाजपा का राजस्थान से सूपड़ा साफ हो रहा है।

कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट पहचान संख्या : एल70109डीएल1980पीएलसी169318
पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 7303495374, ई-मेल : camaccommercial@gmail.com
वेबसाइट : www.camaccommercial.com
30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण
(रूपए लाख में, सिवाय प्रति शेयर डेटा)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30 सितम्बर, 2021 (अलेखापरीक्षित)	अर्द्ध वर्ष समाप्त 30 सितम्बर, 2021 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30 सितम्बर, 2020 (अलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2021 (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	69.35	134.23	136.82	428.14
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा अपवाद मदों से पूर्व)	61.63	118.26	119.43	343.01
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पूर्व (अपवाद मदों के बाद)	61.63	118.26	119.43	343.01
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर तथा अपवाद मदों के बाद	76.88	100.47	100.00	286.98
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	1,299.15	1,395.05	7,760.88	7,373.62
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	88.28	88.28	88.28	88.28
7	अन्य इक्विटी				157,099.28
8	रू. 10/-प्रत्येक के शेयर पर प्रति शेयर अर्जन 1. मूल (रू.)	8.71	11.38	11.33	32.51
	2. तनुकृत (रू.)	8.71	11.38	11.33	32.51

नोट्स :-
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। कम्पनी के वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा 11 नवम्बर, 2021 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी भेजा गया है।
2. 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु उपरोक्त वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित तथा निदेशक मंडल द्वारा 11 नवम्बर, 2021 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित एवं अभिलेखबद्ध किए गए हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु उपरोक्त वित्तीय परिणामों का सीमित पुनरीक्षण किया है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड
हस्ता./-
(स्वाति श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08529725
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11-11-2021

पुणे पुलिस ने एनसीबी के गवाह गोसावी को हिरासत में लिया

पुणे। महाराष्ट्र में पुणे छावनी थाने की पुलिस ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के गवाह किरण गोसावी को वर्ष 2020 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अपनी हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गोसावी को अदालत ने वर्ष 2018 के एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेजा था। अदालत ने उसे पुणे के ही फर्शखाना पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा था। आरोप है कि गोसावी ने मलेशिया के होटल उद्योग में नौकरी दिलाने के नाम पर चिन्मय देशमुख नामक व्यक्ति से 3.09 लाख रुपए की धोखाधड़ी की।

वहीं पुणे छावनी पुलिस थाने में दर्ज मामले में आरोप है कि गोसावी ने वर्ष 2020 में मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लोगों से करीब चार लाख रुपए की धोखाधड़ी की। गोसावी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-420 और 468 के तहत मामला दर्ज किया गया है। छावनी थाने के अधिकारियों ने मंगलवार को अदालत में आवेदन देकर गोसावी की हिरासत देने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया।

छावनी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक कदम ने बृहस्पतिवार को बताया, हमने गोसावी को हमारे थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 17 नवंबर तक पुलिस की हिरासत में भेजा है। गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दो अक्टूबर को क्रूज जहाज पर छापेमारी की कार्वाई करने के बाद गोसावी की अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे।

क्षेत्रीय दलों ने 2019-20 में अज्ञात स्रोतों से जुटाए 445.77 करोड़ रुपए: एडीआर

नई दिल्ली। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि क्षेत्रीय दलों ने 2019-20 में अज्ञात स्रोतों से 445.77 करोड़ रुपए जुटाए, जो उनकी कुल आय का 55.50 प्रतिशत है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 95.616 प्रतिशत या 426.23 करोड़ रुपए चुनावी बांड से आए और क्षेत्रीय दलों ने स्वैच्छिक योगदान से 4.97 करोड़ रुपए एकत्र किए।

रिपोर्ट में कहा गया है, निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास दाखिल दलों के आयकर रिटर्न और चंदे के विवरण के विश्लेषण से पता चलता है कि स्रोत काफी हद तक अज्ञात हैं। वर्तमान में, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम देने वाले लोगों या संगठनों के नाम का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, धन के एक बड़े हिस्से के स्रोत का पता नहीं लगाया जा सकता है और ए धन अज्ञात स्रोतों से हैं।

एडीआर ने कहा कि आप, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) की योगदान रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन इन दलों के चंदे के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उनकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तथा योगदान रिपोर्ट (20,000 रुपए से अधिक का चंदा) में घोषित विसंगतियों को दर्शाते हैं। एडीआर ने कहा कि आप, आईयूएमएल और लोजपा द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घोषित कुल योगदान की राशि उनके द्वारा घोषित कुल चंदा (केवल 20,000 रुपए से अधिक) की राशि से क्रमश: 6.10 करोड़ रुपए, 31.20 लाख रुपए और 4.16 लाख रुपए से कम है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, अज्ञात स्रोतों से क्षेत्रीय दलों की कुल आय 445.77 करोड़ रुपए थी और उनकी कुल आय का 55.50 प्रतिशत थी, जैसा कि उनकी ऑडिट रिपोर्ट में घोषित किया गया। सर्वाधिक अज्ञात आय घोषित करने वाले कुछ शीर्ष क्षेत्रीय दलों में तेलंगाना राष्ट्र समिति (89.158 करोड़ रुपए), तेलगू देशम पार्टी (81.69 करोड़ रुपए), युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसी) (74.75 करोड़ रुपए), बीजू जनता दल (50.58 करोड़ रुपए) और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) (45.50 करोड़ रुपए) शामिल हैं। .एडीआर ने कहा कि ज्ञात चंदा दाताओं से राजनीतिक दलों की कुल आय (निर्वाचन आयोग को दलों द्वारा प्रस्तुत योगदान रिपोर्ट से उपलब्ध चंदा दाताओं का विवरण) 184.62 करोड़ रुपए है, जो इन दलों की कुल आय का 22.98 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य ज्ञात स्रोतों (सदस्यता शुल्क, बैंक ब्याज, प्रचार सामग्री की बिक्री, पार्टी शुल्क आदि) से राजनीतिक दलों को 172.84 करोड़ रुपए की आय हुई।

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-नीलामी
नियम 8 (6) का परंतुक देखें,
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय के लिये ई-नीलामी विक्रय सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पून: निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 8(6) के साथ अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।

सर्वजन तथा व्यक्तिगत रुप से कर्जदार एवं जमानतदार को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शायी गई अचल संपत्ति के संरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/ अधिभारित है उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है एंव दर्शाये विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहॉ है, जैसी है" एवं जैसी है, वैसी है " एवं जिस भी स्थीत में है " के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे है :-

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/ सह-कर्जदारों/ गारंटरों का नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई	बकाया राशि (रू. में)	सुरक्षित मूल्य (रू. में) / धरोहर राशि जमा (रू. में)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
1.	गौतम मलिक (कर्जदार), पुनीत मलिक (सह कर्जदार) लोन खाता नंबर LBDEL00001295071 LBDEL00001295075	एच 307, तीसरी मंजिल, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर पर स्कूटर गैरेज के साथ, नारायना विहार, नई दिल्ली (110028), क्षेत्र 708 वर्ग फीट	रू. 8,54,251/- (अक्टूबर 26, 2021 तक)	रू. 62,00,000/- / रू. 6,20,000/-	नवम्बर 26, 2021 को सु. 11:00 बजे से दो. 01:00 बजे तक	दिसम्बर 04, 2021 को दो. 12:00 बजे से

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी संस्था **मैसर्स नेक्ससेन सॉल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड** की, वेबसाइट **(URL Link https://disposalhub.com)** पर संचालित होगी। बंधकदाताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **दिसम्बर 03, 2021** को **शाम 05.00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अतिंम अवसर दिया जाता है, जिससे विफल रहने पर यह संरक्षित सम्पतियों की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (सारणी ङ संदर्भ करें) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग नई दिल्ली- 110005** में जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावति की स्कैन इमेज सहित दिनांक- **दिसम्बर 03, 2021** तक **शाम 05.00** बजे से पूर्व जमा करे। कृपया नोट करें कि संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहने पर वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग नई दिल्ली- 110005** में निविदा प्रलेखों की हस्तांक्षरित प्रति को दिनांक **दिसम्बर 03, 2021** को **शाम 05.00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट पे आर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैडूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** के पक्ष में **दिल्ली** शाखा में भुगतान हेतु होना चाहिए।

सम्पति अवलोकन, नीलामी के नियम एवं शर्तो तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** को फोन. न. **8126013708** या मैसर्स **नेक्ससेन साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** को फोन. न. **9710029933/ 9810029926/ 01244233933** पर संपर्क करे।

कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसिया **1. नेक्ससेन साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 2. ओजीओ असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड** इस सम्पति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न है।

प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाये किसी एक अथवा अधिक निविदा अथवा बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। बिक्री की विस्तृत नियमो एवं शर्तो हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करे।

तिथि : नवम्बर 12, 2021
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

Fishery subsidies text favours the rich: India

New WTO text fails to protect developing nations' interests, says official

Asit Ranjan Mishra
asit.m@livemint.com
NEW DELHI

India has rejected the revised draft text on World Trade Organization's (WTO's) proposed fishery subsidies agreement, saying it was not balanced and protects the interests of developed nations, while forcing developing countries to make fresh commitments to reduce the paltry subsidies they enjoy.

India has made its stand clear ahead of the crucial 12th ministerial meeting of the WTO. "India is seeking to restrict subsidies of advanced fishing countries, which have led to depletion of fishery resources. India also supports sustainable development of fishery resources. However, the way the current negotiation has happened has moved away from sustainability and the focus seems to be to maintain a standstill," a commerce ministry official said requesting anonymity.

"Advanced countries are trying to maintain their status and privileges. India and other developing countries are trying to point out the inequities and the unfair nature of the text, as well as secure their own interest in the negotiations. We want an agreement to happen but that should be balanced, equitable, fair and it should take care of the livelihood of small fishermen," the official said.

India insists that it needs to have policy space to develop its fishery sector and developed countries responsible for depleting fishing resources should pay upfront along the lines of 'polluter pays'.

"We have also sought carve outs up to our exclusive economic zone (200 nautical miles) and transition periods that are sufficiently long duration. We have said special and differential treatment is required for developing and least developed countries not only to protect livelihoods of poor fishermen but also to address concerns over food security," the official said.

We want an agreement to happen but that should be balanced, equitable, fair and should take care of the livelihood of small fishermen, an Indian official said. MINT

India is not a major fishery subsidy provider. China, the EU and the US offer an annual fishery subsidy of $7.3 billion, $3.8 billion and $3.4 billion, respectively, India offered just $277 million subsidy in 2018 to small fishermen.

"For up to 12 nautical miles from India's coastline, which is territorial water, no discipline should apply on subsidies as most are small fishermen and may not be able to put complicated systems in place. For 12-200 nautical miles, called exclusive economic zones, our view is there must be a carve out and a transition period of 25 years for low-income fishermen. However, the WTO's revised text is proposing a two-year carve out till 12 nautical miles but nothing beyond that for developing countries," he said.

It is clear that distant water fishing is not sustainable without subsidies, the official said. "However, the text unfortunately is again in favour of distant water fishing nations. They should stop subsidies for at least 25 years so that the space left out is optimally utilized by developing countries and least developed countries to develop capacities and to have policy space. If they stop such subsidies, two-thirds of the problem will be resolved. At the same time, 25 years should be available to countries such as India that will be in a position to continue to subsidize in a sustainable manner without demonstrating obligations," he said.

"Those who have created capacity and given subsidy, they should not continue to retain all those privileges and expect that the developing and poor countries to cut subsidies. The text says if you can prove sustainability, you can fish anywhere in the world," he said.

TROUBLED WATERS

ADVANCED countries are trying to maintain their status and privileges, an official said

DEVELOPED nations responsible for depleting fishing resources should pay upfront, he said

INDIA offered just $277 mn subsidy in 2018 to small fishermen compared to billions by others

AHA! A PATTERN! AND SOME MATHEMATICS!

A MATTER OF NUMBERS

DILIP D'SOUZA

Respond to this column at **feedback@livemint.com**

Many years ago, a friend showed me this bit of mathematical trivia that thrilled us both no end: 37 x 3 = 111, 37 x 6 = 222, 37 x 9 = 333, etc.

That may have been my first exposure to the charms of the endless patterns you can make with numbers. Since then, I've run into plenty more. Sample these: 11 x 11 = 121, 111 x 111 = 12321, 1111 x 1111 = 1234321, etc. and 1 x 8 + 1 = 9, 12 x 8 + 2 = 98, 123 x 8 + 3 = 987, 1234 x 8 + 4 = 9876, etc.

And then there's the one I believed, for a while, was my own totally innovative discovery (it wasn't). On your nearest calculator, divide 1 by 7. You'll get 0.142857142 ... actually, the string "142857" repeated endlessly. Here are three reasons I was delighted:

* Indeed, it repeats endlessly. That may have been my first exposure to this phenomenon of repetition. Much later, I learned that while this repetition involves the intriguing idea of infinity, it only means that this is a rational number. Meaning, it can be expressed as a fraction—like 1/7 or 5/113. Still, it startled me that as simple a fraction as 1/7 produced such a marvel.

* Break the repeating unit—142857—into pairs and you have 14, 28 and 57. That little sequence held more charms. Check: 14 is a multiple of 7. So is 28; and 57 is yet another multiple of 7 plus 1. Besides, 28 is twice 14, and 57 is twice 28 plus 1.

* But best of all for me, 2/7, 3/7 and the rest of the 7ths all feature the same digits in the same order, but starting at a different place. Check: 2/7 is 0.285714 ... 3/7 is 0.428571 ... Each subsequent fraction starts at the next-higher digit and preserves the order, all the way till 6/7, which is 0.857142 ... So once I knew the decimal expansion of 1/7, I knew the decimal expansion of the other fractional 7ths. Something about that filled me with wonder.

What does it all mean, though? If patterns like these intrigue you, and you start poking in different mathematical directions, you start finding patterns everywhere. But it goes deeper than their existence, deeper than just finding them. In a very real and fundamental way, the pursuit of mathematics is a constant search for patterns.

Think of ancient humans who first started using a wheel. I imagine the history there must have had a story like this: At some point someone measured the circumference of her wheel and found that it was about 3 times larger than its diameter. Someone else did the same for their smaller wheel and also found that the ratio was about 3. Larger wheel? The same. Any size wheel at all? The same. Aha! A pattern!

Though in fact, as our ancient ancestors must have soon learned, this ratio can never be pinpointed by measurement. There is no fraction that captures it exactly. So it is what we call an irrational number—that enigmatic, wonderful number named π, everybody's favourite mathematical constant.

And if we probably first bumped into π with circles, it turns up unexpectedly in all kinds of mathematical and other corners. Like how certain flu epidemics recur every 20 years (aha! A pattern!), or the way that certain blocks bounce off each other and an enclosing wall (see my column "The fascinating, unexpected appearances of π" bit.ly/3og5tUF).

Or think of prime numbers, those beguiling building blocks of our number system that can only be divided by 1 and themselves. The list starts with 2, 3, 5, 7, 11 ... and goes on to include 103, 2003, 88,069 and many more. In fact, infinitely more. Long ago, the great Greek mathematician Euclid proved elegantly that there's no end to the primes. They get ever sparser as you get to ever higher numbers, but they never run out.

But if you're looking at the primes, it's more than likely you noticed, at some point, twin primes (or prime pairs)—that is, primes that differ by 2 (aha! A pattern!). There's 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, 29 and 31 ... 101 and 103, 617 and 619 and many more. Maybe infinitely more? Are twin primes like the primes themselves—do they never run out?

There's a prime (pun intended) example of a question generated by a pattern; a question that has stimulated endless mathematical research for centuries, and probably will stimulate even more research for a long time to come. Because, in fact, we don't have an answer.

Every mathematician you might ask believes there is an infinity of twin primes—the famous "Twin Prime Conjecture" (TPC)—but nobody has actually proved it (which is why it remains a conjecture). You can measure how captivatingly devilish this conundrum is by the eruption of applause that greeted Yitang Zhang in 2013. For this then-unknown mathematician at the University of New Hampshire had taken a giant step towards proving the TPC. If you consider prime pairs that differ by no more than 70 million, Zhang was able to prove, those are infinite *(bit.ly/3HnJ2Wr)*.

That 70 million has since been whittled down to 246. But not to two, which would prove the TPC.

One more pattern-induced number charmer, to end. Start with the positive integers—1, 2, 3, 4, 5 and so on. Remove every second number, which leaves the odd numbers: 1, 3, 5, 7 and so on. Add them and write down the successive sums: 1, 4, 9, 16 ... Aha! A pattern! These are the squares! (1x1 = 1; 2x2 = 4, 3x3 = 9; 4x4 = 16 and so on).

> If you start poking in different mathematical directions, you find patterns

This particular link between the odd numbers and the squares is well-known, familiar even to young students as they learn basic arithmetic. But now try this. Start with the integers again, but now remove every third number. This gives us:

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 ...

Add them and these are the successive sums:

1, 3, 7, 12, 19, 27, 37, 48, 61, 75 ...

Remove every second number:

1, 7, 19, 37, 61 ...

The successive sums:

1, 8, 27, 64, 125 ... Aha! A pattern! These are the cubes! (1x1x1 = 1, 2x2x2 = 8, 3x3x3 = 27, 4x4x4 = 64, 5x5x5 = 125 and so on).

Wow, and where did that spring from? I'll leave for you the delicious exercise of extrapolating from there to get the fourth powers (1x1x1x1, 2x2x2x2 and so on), the fifth powers, the sixth powers and more.

Amazingly, this remarkable method to generate the powers of numbers was discovered just 70 years ago by Alfred Moessner. For its sheer elegance and simplicity, it's often referred to as Moessner's Miracle. A 2017 article analysing the Miracle, *Moessner's Magical Method (bit.ly/3F5qY15)*, captures the spirit I've been alluding to in this column. It starts with these two sentences: "Amongst the many joys of mathematics are the beautiful patterns that appear unexpectedly from time to time. In 1951, Alfred Moessner discovered a delightful and ingenious way of generating sequences of powers of natural numbers."

Truly delightful. The great G.H. Hardy once said: "A mathematician, like a painter or a poet, is a maker of patterns." Oh yes.

Once a computer scientist, Dilip D'Souza now lives in Mumbai and writes for his dinners. His Twitter handle is @DeathEndsFun

South Indian stars warm up to roles in web originals

Lata Jha
lata.j@livemint.com
NEW DELHI

Top South Indian actors are following their Bollywood counterparts in featuring in web originals, though they belong to an industry that has long acknowledged the dominance of theatres and hero-worship culture originating from wide releases in cinemas.

Telugu star Rana Daggubati will be seen in a Netflix original titled *Rana Naidu* along with uncle and veteran actor Venkatesh. Vijay Sethupathi will feature in *The Family Man* director duo Raj Nidimoru and Krishna DK's next Amazon Prime Video original, while Trisha will appear in a show on SonyLIV called *Brinda*.

Industry experts and platform executives say at least the younger actors are recognizing the enduring appeal of the medium, which is here to stay even as theatres open up and give them opportunities to consolidate their stardom among mainstream audiences. Most southern language offerings are also grabbing more eyeballs than Hindi shows on over-the-top (OTT) streaming platforms, including and beyond native speakers.

"We are seeing the entire southern film ecosystem undergoing a transformative change. As we take the stories to a greater number of viewers and enable a growth in the audience base, the industry itself is expanding. There is a healthy surge with more movies, more TV shows and more digital series being commissioned, opening new avenues for actors and creators, both new and established, to reach beyond the known and explore unchartered territories," said Manish Menghani, head of content licensing, Prime Video India.

Rana Daggubati will be seen in a Netflix original soon.

Like good content, fans also are not restricted by geography or language barriers, Menghani said, referring to the following for southern actors such as Rajinikanth, Mohanlal, Chiranjeevi, Fahadh Faasil and Suriya.

A lot of older, mass-market stars such as Rajinikanth, Vijay and Ajith still swear by theatres, but some of the younger names are happy straddling both worlds, according to independent trade analyst Sreedhar Pillai. An actor like Samantha Ruth Prabhu found herself on the global map after the second season of *The Family Man*, a primarily Hindi language show, Pillai said.

> The pandemic forced many stars to accept the reach that OTT platforms provide across demographics

"Superstars in the south enjoy almost a demigod status. Every release of theirs is like a festival for the fans. They have definitely missed all of this euphoria, which can't be experienced with a pure OTT release," producer and director Vidhyaa B. Reddy said. The pandemic forced many stars to accept the reach that OTT platforms provide across demographics.

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED
Corporate Identity Number : L70109DL1980PLC169318
Regd. Office : I[st] Floor, Express Building, 9-10 , Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
Phone : 7303495374, E-Mail : camaccommercial@gmail.com
Website : www.camaccommercial.com
Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2021
(Rupees in Lakhs except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended Sept 30, 2021 (Unaudited)	Half Year ended Sept 30, 2021 (Unaudited)	Quarter ended Sept 30, 2020 (Unaudited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)
1.	Total income from operations	69.35	134.23	136.82	428.14
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	61.63	118.26	119.43	343.01
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	61.63	118.26	119.43	343.01
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	76.88	100.47	100.00	286.98
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,299.15	1,395.05	7,760.88	7,373.62
6.	Equity Share Capital	88.28	88.28	88.28	88.28
7	Other Equity				157,099.28
8	Earnings per share of Rs 10 each				
	(a) Basic (Rs)	8.71	11.38	11.33	32.51
	(b) Diluted (Rs)	8.71	11.38	11.33	32.51

Notes:-
1 The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results of the Company are available on the website of the Company and has also been sent to The Calcutta Stock Exchange Limited on November 11, 2021.
2 The above Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on November 11, 2021. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the above Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2021.

By Order of the Board
For Camac Commercial Co. Ltd.
Sd/-
(Swati Srivastava)
Director
DIN: 08529225
Place : New Delhi
Date : 11.11.2021

MPMETRO
MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building, Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Barkheda, Bhopal-462022
ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT
Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL), a joint venture of Government of India and Government of Madhya Pradesh is implementing Bhopal Metro Rail Project & Indore Metro Rail Project in the State of Madhya Pradesh.
To meet with the immediate requirement, MPMRCL invites application for the various posts as below on Deputation/ Contract basis.
- Additional General Manager - 01
- Sr. Deputy General Manager - 02
- Deputy General Manager - 01
- Manager - 04
- Assistant Manager - 04

The detailed Vacancy Notification has been uploaded on MPMRCL Website.
Please visit website : **www.mpmetrorail.com.**
Last date for submission of applications is **16th December 2021.**
M.P. Madhyam/102604/2021 **Managing Director**

WBSETCL
WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED
(A Government of West Bengal Enterprise)
Registered Office: Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091
CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: www.wbsetcl.in
E -TENDER FOR ENGAGEMENT OF AGENCIES FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FOR NON CIVIL WORKS
The **General Manager (HR&A)** invites e-Tender from registered, reputed and financially sound Agencies for providing Annual Maintenance Contract for Non Civil works for its units spread across the state of West Bengal. Interested bidders may obtain the bidding documents by registering themselves on the e-tendering portal **(https://wbtenders.gov.in** or **http://etender.wb.nic.in)** from **12.11.21 (11.00 A.M.)** and the e-Tender shall be received (online) up to **01.12.21 (3.00 P.M.)**. Also visit the Company's website **(www.wbsetcl.in)** for details.
NIT No.: GM (HR&A)/WBSETCL/Non Civil (AMC)/2021-22/46 Date: 02.11.2021
ICA- T13980(3)/2021

noida
New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida, G.B. Nagar (U.P.)
Website : www.noidaauthorityonline.com
सार्वजनिक सूचना
एतद सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नौएडा प्राधिकरण के संस्थागत विभाग की योजना कोड Institutional/2021-22 (01) को स्टेट बैंक आफ इन्डिया के आनलाईन ई–आक्शन पोर्टल की वेबसाईट https://property.etender.sbi/ पर दिनांक 12.11.2021 को प्रातः 11.00 बजे से लाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत नर्सिंग होम, सीनियर सेकेन्डरी स्कूल एवं नर्सरी स्कूल के भूखण्डो को आवंटन हेतु सम्मिलिन किया गया है जिनका आवंटन ई–आक्शन प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है। आवेदक योजना में प्रतिभाग किये जाने हेतु वेबसाईट https://property.etender.sbi/ पर रजिस्ट्रेशन कराकर योजना की विवरणिका (नियम व शर्तो) को प्राप्त कर सकता है। योजना में आवेदन एवं ई0एम0डी0 को जमा कराये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 29.11.2021 सायं 05.00 बजे तक निर्धारित है।
(ज्योत्सना यादव)
विशेष कार्याधिकारी–नौएडा
CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

YEIDA FUTURE IS HERE
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ओमेगा–1, (पी–2,) ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com
पत्रांक : वाई0ई0ए0/भूलेख/955/2021 दिनांक: 11.11.2021
सार्वजानिक सूचना
निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है –

सेक्टर–21 के अन्तर्गत प्रस्तावित फिल्म सिटी के फेज–01	
रबपुरा	373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 388/2382, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 406, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 415/2381, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431/1, 431/2, 432, 433, 434, 435, 436, 386/2395, 539, 541, 547, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 558/2386, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 581, 584, 585, 586, 587, 591, 592, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 780.

उपरोक्त सूची में अंकित खसरों से सम्बन्धित कृषकों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि को प्राधिकरण के पक्ष में क्रय की जानी है। अतः प्राधिकरण में उपलब्ध निर्धारित प्रारुप पर सम्बन्धित भूस्वामी अपने प्रार्थना पत्र प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहें।
विशेष कार्याधिकारी

Business News Has A New No.1
52 Million Readers put their trust in livemint.com to make it
India's No. 1 Business News Site